

बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ, अधिक निवेश का वादा भी



प्रो. रामकुमार काकानी
निदेशक, आईआईएम रायपुर

बजट में अच्छे वित्तीय प्रबंधन का नमूना पेश किया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने

बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है। वर्ष 2024 का बजट न केवल कमजोर वर्गों के लिए समावेशी है, बल्कि राज्य में अधिक निवेश का वादा भी करता है। यह सब अच्छे वित्तीय प्रबंधन के तहत किया जा रहा है। पिछले साल केंद्रीय बजट में पूंजी परिव्यय के लिए बड़े पैमाने पर प्रावधान किया गया था और इसी तर्ज पर, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के पहले राज्य बजट में 22,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जो कुल बजट का 15% है। औसत परिव्यय 12 प्रतिशत से अधिक है। ध्यान दें कि पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों के निर्माण द्वारा लंबे समय में राज्य के

पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख घरों का निर्माण, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रति वर्ष 12 हजार करोड़ रुपए और राज्य के किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

विकास को सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है, जो बदले में न केवल विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है, बल्कि परिसंपत्तियों के निर्माण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप रोजगार सृजन भी होगा। शुद्ध राजकोषीय घाटा राज्य जीएसडीपी का 2.9% अनुमानित है, जो एफआरबीएम

अधिनियम में निर्धारित 3% सीमा के भीतर है। यह दर्शाता है कि व्यय की दृष्टि और परिव्यय राजकोषीय रूप से जिम्मेदार होने के द्वारा किया जाता है। बजट ने संकेत दिया कि सरकार को बिना किसी नए कर वृद्धि या बदलाव के 22% की राजस्व वृद्धि की उम्मीद है जो उत्कृष्ट है क्योंकि यह कराधान के मामले में

व्यवसायों के लिए अनिश्चितता को कम करता है। आज बजट में एक प्रमुख घोषणा 'इन्वेस्ट छत्तीसगढ़' कार्यक्रम के आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये के पैकेज स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि छत्तीसगढ़ संसाधनों से समृद्ध राज्य है और इसमें आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी जैसे प्रमुख कौशल संस्थान भी हैं। ये अधिक से अधिक कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। व्यापारिक घरानों से निवेश और एफडीआई। इसलिए आने वाले वर्षों में राज्य के लिए एक महान विकास पथ को आकार देना है। कमजोर वर्ग के लिए आगे देखने के लिए बहुत कुछ है।